'जनता पानी के लिये परेशान हुई तो जिम्मेदार अफसरों की खैर नहीं'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने बढ़ती गर्मी में पेयजल सप्लाई की मैराथन बैठक ली

जयपुर, 10 अप्रेल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, तापमान में अचानक हुई बढ़ोतरी के बाद, पेयजल की मांग और उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा के लिए गुरुवार दोपहर मुख्यमंत्री निवास पर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि गर्मी में जनता को अगर पानी के लिए परेशान होना पड़ा, तो जिम्मेदार अफसरों की खैर नहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में गर्मी तेजी से बढ़ी है, ऐसे में आमजन को बढ़ी हुई मांग के अनुसार पर्याप्त पेयजल मुहैया करवाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिला कलैक्टर कन्टिन्जैंसी प्लान के अनुसार पेयजल प्रबंधन स्वयं की देखरेख में सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शहरी के साथ-साथ, ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी की किसी तरह की किल्लत नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि अंतिम छोर के उपभोक्ताओं को भी पेयजल की कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में पीएचईडी के फील्ड अधिकारी एवं कर्मचारी मुख्यालय पर उपस्थित रहें और बिना सक्षम अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ें।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी में पेयजल की मांग और उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा के लिए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि गर्मी में जनता को पानी के लिए परेशान होना पड़ा, तो जिम्मेदारों की खैर नहीं।

- **सभी कलैक्टरों को कन्टिन्जैंसी प्लान के अनुसार, पेयजल प्रबंधन स्वयं की देखरेख में सुनिश्चित करने व शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी की किल्लत नहीं होने देने के निर्देश दिये।**

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गर्मी को देखते हुए नए हैण्डपम्प, नलकूप लगाने, पुराने हैण्डपम्प, नलकूपों की मरम्मत, पाइपलाइनों को दुरस्त करने सहित, पेयजल आपूर्ति सुदृढ़ीकरण के सभी कार्य 15 मई से पहले हर हाल में पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि पेयजल समस्या के समाधान के लिए जिला कलैक्टरों को एक-एक करोड़ रुपए का अनटाइड फंड उपलब्ध करवाया गया है।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (पीएचईडी) भास्कर ए. सावंत ने बताया कि विभाग की वृहद् परियोजनाओं में कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध तरीके से इनके कार्य करवाए जा रहे हैं।

'बाल आयोग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में कहा गया कि आयोग अध्यक्ष का कार्यभार किसी आईएएस अधिकारी को देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। विभाग की साल 2010 की अधिसूचना के तहत यदि अध्यक्ष का पद खाली होता है तो उसका कार्यभार आयोग के वरिष्ठ सदस्य को दिया जाता है। याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं आईएएस कुलदीप रांका को बिना किसी प्रावधान अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा गया है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता आयोग की वरिष्ठ सदस्य हैं।

'मोदी सरकार बेवजह झूठी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चार्जशीट राणा सहित 9 आरोपियों के खिलाफ दायर की गई थी। स्पेशल एनआइए कोर्ट ने दिल्ली में गैर जमानती वॉरंट जारी किए और इंटरपोल से फरार अपराधियों की गिरफ्तारी में मदद मांगी गई।

पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि यह सारी कवायद शांति से हो रही कानूनी कूटनीति थी न कि मीडिया स्टंट। वर्ष 2012 में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और विदेश सचिव रंजन मथाई ने अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन व अंडर सैक्रेटरी वैंडी शरमन के समक्ष तहव्वुर राणा और हेडली का मुद्दा उठाया। जनवरी 2013 में हेडली को 35 साल की जेल हो गई और राणा को पहले ही जेल हो चुकी थी। भारत ने जोरदार तरीके से हेडली के प्रत्यर्पण की मांग उठाई। यूपीए सरकार ने उसकी सजा पर निराशा जताई।

अमेरिका में भारत की राजदूत निरुपमा राव लगातार यह मुद्दा उठाती रहीं। वर्ष 2015 में हेडली 26/11 केस में गवाह बन गया। वर्ष 2016 में मुम्बई कोर्ट ने उसे पूर्ण सहयोग की शर्त पर माफी दे दी, जिससे जैबुद्दीन अंसारी (अबु जुंडाल) के खिलाफ केस तैयार करने में मदद मिली।

दिसम्बर 2018 में, कानूनी बाधाओं के समाधान के लिये, एक टीम अमेरिका गई थी तथा जनवरी 2019 में एक बार फिर कहा गया था कि राणाको अपनी पूरी सजा अमेरिका में ही काटनी होगी। सजा में गुजरे समय को ध्यान में रखते हुये, उसकी रिहाई 2023 में तय हुई थी। ये "स्ट्रॉंग लीडर" क्षण नहीं, बल्कि न्याय के मंद गति से चलने वाले पहिये हैं, जो सालों की मेहनत से आगे बढ़ते हैं। चिदम्बरम को यह बात समझाने में काफी कष्ट उठाना पड़ा।

उन्होंने कहा, जून 2020 में, स्वास्थ्य कारणों से हुई राणा की रिहाई के बाद, भारत सरकार ने उसकी गिरफ्तारी का आग्रह किया। बाइडन सरकार ने उसके प्रत्यर्पण का समर्थन किया। मई, 2023 में, अमेरिकन अदालत ने "अमेरिका-भारत प्रत्यर्पण समझौते" के तहत, उसका प्रत्यर्पण प्रमाणित कर दिया। राणा ने अपील की और कई याचिकाएं दायर कीं, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी शामिल थी, और अंत में, दोहरी जोखिम का हवाला देते हुये, एक रिट याचिका अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में लगाई। उसकी सारी याचिकाएँ खारिज कर दी गईं। अंतिम इनकार, डॉनल्ड ट्रम्प के शपथ-ग्रहण समारोह के एक दिन बाद, 21 जनवरी, 2025 को किया गया।

फरवरी 2005 में, प्रधानमंत्री मोदी तथा राष्ट्रपति ट्रम्प ने एक प्रैस कॉन्फ्रैंस में एक साथ खड़े होकर, उस चीज का श्रेय लेने की कोशिश की, जो मूलतः यूपीए काल के कई सालों के ग्राउन्ड वर्क का परिणाम था। भारतीय अधिकारियों ने 17 फरवरी तक 26/11 के षडयंत्र में राणा की भूमिका की पुष्टि कर दी थी। यह पुष्टि काफी पहले, 2005 में ही कर दी गई थी। जब वह एलईटी तथा आईएसआई के सदस्यों के बीच समन्वय का कार्य कर रहा था। अन्त में, 8 अप्रैल 2025 को, अमेरिकन अधिकारियों ने राणा को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया। वह 10 अप्रैल को नई दिल्ली आ गया।

तथ्य स्पष्ट होने ही चाहिये- मोदी सरकार ने इस प्रक्रिया की पहल नहीं की, न ही इसने कोई नया ब्रेक थ्रू ही किया। इसने तो केवल यूपीए-काल में शुरु की गई परिपक्व, सतत एवं रणनैतिक कूटनीति का लाभ लिया। यह प्रत्यर्पण किसी "ग्रान्ड स्टैन्डिंग" का परिणाम नहीं है। यह तो एक ऐसा विधान है, जिसे भारत सरकार प्राप्त कर सकती है, जब कूटनीति, विधि-प्रवर्तन (लॉ एनफोर्समैंट) तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में पूरी नेकनीयती से आगे बढ़ा जाता है तथा इसमें अपनी पीठ थपथपाने जैसे कोई चीज नहीं होती। तथ्यों को आम जनता तक पहुँचाते हुये, यह बयान समाप्त हुआ।

क्या टैरिफ वॉर के कारण भारत को...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके, जो कि "मेक इन इण्डिया" पहल के अनुरुप होगा।

वैश्विक व्यापार में हो रहे बदलाव कृषि और श्रम कानूनों में भी सुधार को गति दे सकते हैं, जिन्हें भारत में अक्सर द्वितीय पीढ़ी के सुधारों के रुप में देखा जाता है। इन क्षेत्रों में नए दबावों से निपटने के लिए, भारत लचीले श्रम कानूनों और कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार ला सकता है, जिससे किसानों को वैश्विक बाज़ारों से बेहतर तरीके से जुड़ने का अवसर मिले और अक्षम व्यवस्थाओं को कम किया जा सके।

ट्रेड का बदलता परिदृश्य भारत को डिजिटाइज़ेशन और टैक्नोलॉजिकल इनोवेशन (नवाचार) पर भी ध्यान केन्द्रित करने को प्रेरित कर सकता है।

इस क्षेत्र में द्वितीय पीढ़ी के सुधारों में, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, ई-कॉमर्स रैगुलेशन्स को सरल करना और आर्टिफिशल इन्टैलिजैंस (ए.आई.) तथा ऑटोमेशन में निवेश आदि शामिल हो सकते हैं। इससे भारत को ग्लोबल टैक्नोलॉजिकल सैंटर के रुप में स्थापित होने में मदद मिलेगी, विशेषकर, यदि पारंपरिक निर्माण उद्योग अमेरिका में अधिक टैरिफ का सामना करते हैं।

इसके अलावा, भारत शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों में सुधार करके मानव संसाधन को भी मजबूत बना सकता है। द्वितीय पीढ़ी के सुधारों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्टैम (साइन्स, टैक्नॉलजी, इंजीनियरिंग एण्ड मैथमैटिक्स) शिक्षा में निवेश, और वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करने वाली नीतियाँ शामिल हो सकती हैं। ये सुधार टैक्नॉलजी और हरित ऊर्जा जैसे उभरते उद्योगों में भारत को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिला सकते हैं।

नई टैरिफ नीति भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संतुलन को भी प्रभावित कर सकती है, और इसके जवाब में भारत विदेशी निवेश और टैक्नॉलजी ट्रांसफर को आकर्षित करने वाले सुधार लागू कर सकता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बाधाओं को दूर करके और निवेश-अनुकूल वातावरण बनाकर, भारत वैश्विक व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना रह सकता है।

तथापि, भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव के साथ तालमेल बिठाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर भारत अपने उद्योगों को सशक्त बनाना चाहता है, उसे एक ऐसे वैश्विक परिदृश्य में प्रतिस्पर्धी बने रहना होगा, जहाँ "ट्रेडिशनल ट्रेड पैटर्न" बदल रहे हैं। इसके अलावा, द्वितीय पीढ़ी के सुधारों की गति को राजनीतिक और नौकरशाही शक्तियों से भी विरोध झेलना पड़ सकता है, विशेषकर कृषि, श्रम और भूमि सुधारों जैसे क्षेत्रों में। अमेरिका की शुल्क नीति से उत्पन्न व्यापक वैश्विक आर्थिक अस्थिरता भी भारत के लिए जोखिम पैदा कर सकती है, जिससे सावधानी से निपटना होगा।

इस प्रकार, अमेरिका की नई शुल्क नीति भारत को द्वितीय पीढ़ी के सुधारों को तेज करने के लिए प्रेरित कर सकती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में, जो घरेलू प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार, और व्यापारिक साझेदारियों में विविधता लाने में सहायक हो सकती है। भारत की प्रतिक्रिया रणनीतिक सुधारों का एक मिश्रण हो सकती है, जैसे निर्माण, कृषि, श्रम कानून और व्यापार नीतियां, जो वैश्विक व्यापार परिवर्तनों के प्रति अर्थव्यवस्था को अधिक लचीला बना देंगी। ये सुधार भारत के, 21 वीं सदी में वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के, दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुरुप होंगे।

गृह मंत्री चेन्नई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यह थी कि अन्नामलाई के साथ काम करना उसके लिये मुश्किल होगा तथा वह राज्य भाजपा के अध्यक्ष के रुप में अन्नामलाई के अलावा, किसी अन्य नेता के साथ डील करना पसंद करेगी।

चूँकि अब अन्नामलाई अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं, इस महत्वपूर्ण पद के लिये अन्य नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। इस पद की दौड़ में विधायक नैनार नागेन्द्रन काफी आगे हैं, लेकिन अभी उन्हें पार्टी में आये 10 वर्ष नहीं हुये हैं, जबकि पार्टी नियमों के अनुसार, इस पद के लिये यह भी एक शर्त है। जयललिता तथा पन्नीर सेल्वम सरकारों में मंत्री रह चुके नागेन्द्रन, इस समय विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता हैं।

इस दौड़ में कोयम्बटूर दक्षिण की विधायक वनन्ती श्रीनिवासन, जो एक प्रतिष्ठित वकील भी हैं, भी शामिल हैं। वे इस समय भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तथा 2022 से पार्टी की केन्द्रीय चुनाव समिति की सदस्य भी हैं। उनका नाम उस समय विशेष रुप से उभरकर सामने आया था, जब उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनावों में जाने -माने अभिनेता कमल हासन को हराया था।

भाजपा की तमिलनाडु इकाई के पूर्व अध्यक्ष तमिलिसाई सौंदरराजन तथा केन्द्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन भी इस दौड़ में शामिल हैं। मुरुगन भी पहले राज्य भाजपा अध्यक्ष रह चुके हैं।

विश्व सदमे में है, पहले अमेरिका...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नहीं था, यानी, अमेरिकी सरकार वित्तीय बाज़ार से ऋण जुटाने में असफल हो रही थी।

जैसा कि सर्वविदित है, दुनिया भर की सरकारें अपने बकाया ऋणों का भुगतान वास्तव में कभी नहीं करतीं, वे केवल नया ऋण लेकर पुराने ऋण का भुगतान करती हैं। इस फंड की इस गतिविधि के बिना सरकारें ठप पड़ जाएँगी।

टैरिफ के कारण वित्तीय बाज़ारों में मची खलबली ने इस संभावना को जन्म दिया कि ट्रेज़री मार्केट पूरी तरह से ठप्प हो सकता है। इस संभावना को देखकर ट्रंप को अपनी गलती का अहसास हुआ और उन्होंने तुरंत अपनी टैरिफ योजना को स्थगित करने का आदेश दिया। अमेरिकी बॉन्ड मार्केट की स्थिति ही कारण वह बनी, जिसने ट्रंप को पूरी तरह से अपने निर्णय को पलटने के लिए मजबूर किया।

दूसरी ओर, एक और बड़ा कारण यह था कि फोन की घंटियों की बाढ़ आ गई थी- यानी व्यापारिक अधिकारियों और उद्योगपतियों के फोन कॉल्स की भरमार थी, जो इस नीति को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे।

इन कॉल्स के जरिए अमेरिकी उद्योग और व्यापार जगत के नेता ट्रंप को इस नीति को आगे न बढ़ाने की सलाह दे रहे थे।

इनमें प्रमुख आवाज़ थी जेपी मॉर्गन इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रमुख जैमी डिमोन की, जिन्होंने अपने वार्षिक पत्र में बैंक के शेयरधारकों को बहुत संयमित रुप में आगाह किया कि अमेरिका "नींद में चलते हुए मंदी की ओर बढ़ रहा है।"

ऐसे और भी कई लोगों ने इस संभावना की ओर इशारा किया था, जिनमें प्रमुख अर्थशास्त्री और पूर्व ट्रेजरी सचिव लैरी समर्स भी शामिल थे, जिन्होंने ट्रंप के आर्थिक पैकेज के बाद मंदी आने की भविष्यवाणी की थी।

"मंदी" शब्द अमेरिका के लिए डरावना है। इसका मतलब होता है- रोजगार और आय की हानि, बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी और वित्तीय बाज़ारों में उथल-पुथल। ये वही भयावह आर्थिक स्थितियाँ हैं, जो 1930 के दशक की महामंदी से जानी जाती हैं।

यहाँ तक कि ट्रंप के कुछ करीबी सहयोगी और समर्थक भी यह मानने लगे थे कि अमेरिका मंदी की ओर बढ़ रहा है, और एक बार यह शुरु हो गई तो कोई नहीं जानता कि यह कब और कहाँ जाकर रुकेगी।

इसके अलावा, कुछ शुरुआती परिणाम भी दिखने लगे थे। तेल की कीमतें गिर गई थीं और अमेरिका तेल का प्रमुख निर्यातक है। तेल और गैस उद्योग अमेरिकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। चीन को अमेरिका से तेल का निर्यात लगभग रुक चुका था, जिससे बाज़ार में अधिशेष (ग्लट) की स्थिति बन सकती थी।

कुल मिलाकर, डॉनल्ड ट्रंप की छवि को सीधा नुकसान हुआ है और वे अब अपनी हार के ज़ख्म सहला रहे हैं, हालांकि वे यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ उनकी योजना का हिस्सा था। घमंड का बुरा अंजाम।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908